HINDI FILE

SIX SIGMA IAS

Dream | Dare | Deliver

DREAM FOR NATION | DARE TO SERVE | DELIVER WITH INTEGRITY

DAILY PRACTICE QUESTIONS

BEST FOR UPSC | UP PCS EXAM

DATE : AUGUST 22, 2026

Comprehensive Coverage | Exam-Focused Analysis | Concept Clarity & Insights | Practice MCQs with Explanation | Daily Updates, Better Results

CONTACT INFO:
+91 92896 33341 | +91 96679 33341

EMAIL ID:
info@sixsigmaias.com

WEB PAGE:
www.sixsigmaias.com

ADDRESS:
C-6, GROUND FLOOR, SECTOR 2,
NEAR SECTOR 15 METRO STATION, NOIDA – 201301, UTTAR PRADESH

दैनिक अभ्यास प्रश्न - स्थैतिक भाग से

प्रश्न–1 : विजयनगर साम्राज्य के संबंध में विचार करें :

1. कथन 1 : विजयनगर शासनकाल में प्रचलित "अमरा-नायक प्रणाली" मध्यकालीन यूरोप की सामंती व्यवस्था से मिलती-जुलती थी, किन्तु इसमें राजा का केन्द्रीय नियंत्रण अधिक सख्त था।
2. कथन 2 : कृष्णदेवराय के शासन में निर्मित "महानवमी डिब्बा" विजयनगर शासकों की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक था, क्योंकि इसका उपयोग हिन्दू–मुस्लिम संयुक्त अनुष्ठानों हेतु किया जाता था।

सही विकल्प चुनिए :
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2
उत्तर : (a) केवल 1
व्याख्या :
○ अमरा-नायक प्रणाली वास्तव में यूरोपीय सामंतवाद से मिलती-जुलती थी; अमरा-नायकों को भूमि-राजस्व के बदले सैन्य सेवा देनी होती थी तथा उन्हें स्थानीय शक्ति विकसित न करने देने हेतु समय-समय पर स्थानांतरित किया जाता था।
○ "महानवमी डिब्बा" का प्रयोग राजकीय समारोहों, विजय उत्सव और नवरात्रि अनुष्ठानों के लिए किया जाता था, न कि सामूहिक हिन्दू–मुस्लिम पूजा के लिए। इसलिए कथन 2 गलत है।

प्रश्न–2 : भारत में मैंग्रोव (Mangroves) के संबंध में विचार करें :

1. कथन 1 : भारत में मैंग्रोव केवल मुहानों (estuaries) एवं डेल्टा क्षेत्रों की उच्च लवणता वाली भूमि में पाए जाते हैं, अंतःस्थलीय (inland) लवणीय दलदलों में नहीं।
2. कथन 2 : 'सुंदरबन' (युनेस्को विश्व धरोहर स्थल) भारत का एकमात्र मैंग्रोव प्रदेश है, जहाँ प्राकृतिक रूप से बाघ पाए जाते हैं।
3. कथन 3 : मैंग्रोव कार्बन अवशोषण के प्रमुख भंडार (carbon sinks) हैं और इन्हें "नीला कार्बन पारितंत्र" (blue carbon ecosystems) का अंग माना जाता है।

सही विकल्प चुनिए :
(a) 1 और 2 केवल
(b) 2 और 3 केवल
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर : (b) 2 और 3 केवल
व्याख्या :
○ कथन 1 गलत है → **मैंग्रोव अंतःस्थलीय लवणीय दलदल एवं ज्वार भाटे वाले कीचड़** (inter-tidal mudflats) में भी पाये जाते हैं।
○ कथन 2 सही है → **सुंदरबन वह अद्वितीय क्षेत्र है जहाँ शेर (रॉयल बंगाल टाइगर) प्राकृतिक रूप से मैंग्रोव वनों में पाया जाता है।**
○ कथन 3 सही है → **मैंग्रोव अपनी जैव-भार एवं अवसादों** (sediments) में विशाल मात्रा में कार्बन संचित करते हैं; ये समुद्री घास (seagrass) एवं लवणीय घासभूमि (salt marshes) सहित नीले कार्बन पारितंत्र का अंग हैं।

प्रश्न–3 : भारत के भुगतान संतुलन (Balance of Payments – BoP) के संदर्भ में विचार करें :

1. कथन 1 : चालू खाते (current account) में अधिशेष का अर्थ यह है कि देश के माल व सेवा निर्यात सदैव आयात से अधिक हैं।
2. कथन 2 : भारत में पूँजी खाते (capital account) में घाटा सदैव विदेशी पूँजी के शुद्ध बहिर्गमन (outflow) का द्योतक है।
3. कथन 3 : भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप करता है, जो भुगतान संतुलन में प्रत्यक्षतः भंडार में परिवर्तन (change in forex reserves) के रूप में परिलक्षित होता है।

सही विकल्प चुनिए :
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर : (c) केवल 3
व्याख्या :
○ कथन 1 गलत है → चालू खाते में अधिशेष केवल निर्यात की अधिकता से नहीं, बल्कि अप्रवासी भारतीयों से प्राप्त भारी प्रेषण (remittances) आदि के कारण भी हो सकता है।
○ कथन 2 गलत है → पूँजी खाते में घाटा सदैव विदेशी पूँजी बहिर्गमन दर्शाता हो यह आवश्यक नहीं; यह विदेशी ऋण अदायगी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के स्तर में परिवर्तन या बाहरी ऋण की स्थिति के कारण भी हो सकता है।
○ कथन 3 सही है → RBI द्वारा विदेशी मुद्रा की ख़रीद–फरोख़्त का सीधा प्रभाव भुगतान संतुलन खाते में "भंडार परिवर्तन" (change in reserves) के रूप में दर्ज होता है।

प्रश्न–4 : भारत के राज्यपाल के पद के संबंध में विचार करें :
1. कथन 1 : राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है, किन्तु यदि हटा दिया जाए तो यह मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता; इस विषय को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है।
2. कथन 2 : संविधान का अनुच्छेद 153, एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने की अनुमति देता है।
3. कथन 3 : राज्यपाल हर मामले में मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से बाध्य रहते हैं, किसी प्रकार का अपवाद नहीं है।
4. कथन 4 : सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने का राज्यपाल का अधिकार न्यायिक समीक्षा (judicial review) के अधीन नहीं है।

सही विकल्प चुनिए :
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) केवल 2, 3 और 4
उत्तर : (a) केवल 1 और 2
व्याख्या :
○ कथन 1 सही है → भारतीय संविधान (अनुच्छेद 156) में राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छानुसार पद पर रहते हैं, किन्तु *बी. पी. सिंगल प्रकरण (2010)* में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हटाने की प्रक्रिया मनमानी नहीं हो सकती और यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है।
○ कथन 2 सही है → अनुच्छेद 153 स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
○ कथन 3 गलत है → राज्यपाल कुछ विषयों (जैसे विवेकाधीन शक्तियाँ) में मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य नहीं हैं।
○ कथन 4 गलत है → सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, राज्यपाल का किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने का निर्णय भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है।

प्रश्न–5 : कारण–तर्क (Assertion–Reason) प्रकार
- कथन (A) : दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट की अपेक्षा अधिक वर्षा प्राप्त होती है।
- तर्क (R) : पश्चिमी घाट अरब सागर तट के लगभग समांतर स्थित हैं तथा उनका पवनाभिमुखी भाग (windward side) आर्द्र मानसूनी पवनों को प्रत्यक्ष रूप से रोकता है।

सही विकल्प चुनिए :
(a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A का सही कारण है।
(b) A और R दोनों सही हैं, किन्तु R, A का सही कारण नहीं है।
(c) A सही है किन्तु R गलत है।
(d) A गलत है किन्तु R सही है।
उत्तर : (a) A और R दोनों सही हैं तथा R, A का सही कारण है।
व्याख्या :
○ पश्चिमी घाट अरब सागर के समानांतर उठते हैं और अचानक पर्वतीय अवरोध उत्पन्न करते हैं। नमी से भरी दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी हवाएँ इनके पवनाभिमुखी भाग से टकराती हैं, जिससे प्रचुर मात्रा में पर्वतीय (ओरोग्राफिक) वर्षा होती है।
○ पूर्वी घाट अपेक्षाकृत निम्न, टूटे-फूटे तथा मानसूनी हवाओं की दिशा से प्रत्यक्ष संरेखित न होने के कारण कम वर्षा प्राप्त करते हैं।

दैनिक अभ्यास प्रश्न – करंट अफेयर्स अनुभाग से

प्रश्न 1: भारत की हरित हाइड्रोजन प्रमाणीकरण योजना (Green Hydrogen Certification Scheme – GHCI) के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए :

1. यह योजना, हरित हाइड्रोजन के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं दोनों को अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (Renewable Energy Certificates – RECs) जारी करती है, जिससे इसके उपयोग को प्रोत्साहन मिले।
2. इस योजना के अंतर्गत प्रमाणन केवल उन्हीं उत्पादकों को मिलता है जो पूर्णतः अक्षय ऊर्जा (जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा) से हाइड्रोजन उत्पादन करते हैं, और इसमें ग्रिड-आधारित विद्युत को मान्यता नहीं दी जाती।

सही विकल्प चुनिए :
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2
उत्तर : (d)
व्याख्या :

- कथन 1 गलत है :
  - GHCI अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र (RECs) जारी नहीं करती।
  - यह केवल हरित हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करने के लिए विशिष्ट प्रमाणपत्र (Certificates) देती है, जो उत्सर्जन तीव्रता (प्रति कि.ग्रा. हाइड्रोजन पर उत्सर्जित CO_2) पर आधारित होते हैं।
- कथन 2 गलत है :
  - GHCI में ग्रिड-संलग्न (Grid-connected) अक्षय ऊर्जा का भी प्रयोग मान्य है, बशर्ते उचित लेखांकन किया जाए।
  - इसका आधार केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि उत्सर्जन सीमा (Emission Threshold) है।

प्रश्न 2: हाल ही में समाचारों में रही 'लाल-शीर्ष कछुआ' (Red-Crowned Roofed Turtle – *Batagur kachuga*) किस प्रकार की प्रजाति है?
(a) लद्दाख के हिमालयी उच्च ऊँचाई वाले आर्द्रभूमि क्षेत्रों की स्थानिक (Endemic) प्रजाति
(b) गंगा नदी घाटी की अत्यंत संकटग्रस्त (Critically Endangered) मीठे पानी की कछुआ प्रजाति
(c) भारत के पूर्वी तट पर अंडे देने वाली समुद्री कछुआ प्रजाति
(d) CITES परिशिष्ट-II (Appendix-II) के अंतर्गत संरक्षित लेकिन भारतीय कानून में संरक्षित न होने वाली नरम खोल वाली (Soft-shelled) कछुआ प्रजाति
उत्तर : (b)
व्याख्या :

- यह गंगा तथा उसकी सहायक नदियों (भारत और बांग्लादेश) में पाई जाने वाली मीठे पानी की कछुआ प्रजाति है।
- स्थिति : IUCN वर्गीकरण के अनुसार *Critically Endangered*।
- कानूनी संरक्षण :
  - वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की *अनुसूची-I* में शामिल।
  - CITES परिशिष्ट-I में भी संरक्षित।
- यह समुद्री कछुआ नहीं है।

प्रश्न 3: अमेज़न के "प्रोजेक्ट काइपर" (Project Kuiper) के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए :

1. इसका उद्देश्य निम्न-पृथ्वी कक्षा (Low Earth Orbit – LEO) में उपग्रहों का समूह स्थापित कर वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करना है।

2. यह सीधे तौर पर OneWeb तथा Starlink की प्रतिस्पर्धी परियोजना है तथा इसे अमेरिकी संघीय संचार आयोग (FCC) से स्वीकृति प्राप्त है।
3. Starlink से भिन्न, प्रोजेक्ट काइपर के उपग्रह केवल भू-स्थिर कक्षा (Geostationary Orbit – GEO) में संचालित होंगे ताकि स्थिर कवरेज सुनिश्चित किया जा सके।

सही विकल्प चुनिए :
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर : (a)
व्याख्या :

- कथन 1 सही है :
  - प्रोजेक्ट काइपर अमेज़न की योजना है जो LEO उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान करता है।
- कथन 2 सही है :
  - यह Starlink और OneWeb का प्रतिद्वंद्वी है एवं FCC द्वारा लगभग 3,000 उपग्रहों की अनुमति दी गई है।
- कथन 3 गलत है :
  - उपग्रह केवल भू-स्थिर कक्षा (GEO) में नहीं, बल्कि Starlink की तरह LEO में कार्य करेंगे, ताकि विलंब (Latency) कम हो।

प्रश्न 4: नागपुर के रघुजी भोंसले प्रथम के संबंध में विचार कीजिए :
1. उन्होंने 18वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार के कुछ हिस्सों तक मराठा प्रभाव को विस्तार दिया।
2. उन्होंने 1757 के प्लासी युद्ध (Battle of Plassey) में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों से युद्ध किया।
3. उनके आक्रमण प्रायः चौथ और सरदेशमुखी वसूलने हेतु होते थे, न कि स्थायी क्षेत्रीय विजय के लिए।

सही विकल्प चुनिए :
(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 1 और 3
(c) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3
उत्तर : (b)
व्याख्या :

- कथन 1 सही है :
  - रघुजी भोंसले (1740–1755) ने मराठा प्रभाव बंगाल, उड़ीसा और बिहार तक पहुँचाया।
- कथन 2 गलत है :
  - 1755 में उनकी मृत्यु हो गई थी, अतः उन्होंने 1757 के प्लासी युद्ध में भाग नहीं लिया।
- कथन 3 सही है :
  - उनके अभियानों का उद्देश्य मुख्यतः चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलना था, न कि क्षेत्रों पर स्थायी अधिकार करना।

प्रश्न 5: संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रकाशित 'स्पेशल 301 रिपोर्ट' (Special 301 Report) से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए :
1. यह वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों (Intellectual Property Rights – IPR) की सुरक्षा एवं प्रवर्तन की वार्षिक समीक्षा है।
2. इस रिपोर्ट में *प्राथमिक निगरानी सूची* (Priority Watch List) में आने वाले देशों पर स्वचालित रूप से व्यापारिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
3. भारत कई बार इस रिपोर्ट की प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया गया है।
4. यह रिपोर्ट 1974 के यूएस ट्रेड एक्ट (US Trade Act, 1974) की धारा 301 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से प्रकाशित की जाती है।

सही विकल्प चुनिए :
(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 1, 3 और 4
(c) केवल 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4
उत्तर : (b)

व्याख्या :

- कथन 1 सही है :
  - यह अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (USTR) की वार्षिक रिपोर्ट है, जो IPR संरक्षण व कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करती है।
- कथन 2 गलत है :
  - प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल होना स्वचालित प्रतिबंध का कारण नहीं बनता; यह केवल गहन निगरानी का संकेतक है।
- कथन 3 सही है :
  - भारत को फ़ार्मास्युटिकल पेटेंट एवं कॉपीराइट विवादों के कारण बार-बार इस सूची में रखा जाता है।
- कथन 4 सही है :
  - यह रिपोर्ट अमेरिका के 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 के अंतर्गत प्रकाशित होती है।

प्रश्न 6: 'बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान' (Bandhavgarh National Park), जो हाल ही में बाघ संरक्षण प्रयासों के लिए चर्चा में रहा है, कहाँ स्थित है?

(a) उत्तरी छत्तीसगढ़, हसदेव अरण्य वनों के समीप
(b) पूर्वी मध्य प्रदेश, विन्ध्य पर्वतमाला में
(c) दक्षिणी उत्तर प्रदेश, सोन नदी बेसिन के किनारे
(d) उत्तरी ओडिशा, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिज़र्व के समीप

उत्तर : (b)

व्याख्या :

- बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया ज़िले (पूर्वी भाग) में स्थित है।
- यह विन्ध्य पर्वतमाला का हिस्सा है।
- विशेषताएँ :
  - भारत में बाघों की उच्च घनत्व (High Tiger Density) के लिए प्रसिद्ध।
  - यहाँ ऐतिहासिक बांधवगढ़ किला स्थित है।

दैनिक अभ्यास हेतु विषय आधारित प्रश्न

GS–1 (विश्व इतिहास)

प्रश्न 1.

"वियना कांग्रेस (1815) ने यूरोप में शक्ति संतुलन तो स्थापित किया, परंतु यह राष्ट्रीयता (Nationalism) की आकांक्षाओं को संबोधित करने में विफल रही।" आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर का रूपरेखा

- परिचय :
  - वियना कांग्रेस (1815) का आयोजन नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप में शांति बहाल करने और राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ।
  - यह तत्काल संघर्षों को रोकने में सफल अवश्य रहा परंतु राष्ट्रीयतावादी और उदारवादी आंदोलनों की वास्तविक आकांक्षाओं की उपेक्षा की, जिससे भविष्य में अनेक क्रांतियाँ हुईं।
- सकारात्मक परिणाम :
  - फ्रांस, स्पेन एवं इटली में राजशाही का पुनःस्थापन।
  - विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु "कंसर्ट ऑफ यूरोप" की स्थापना।
  - सीमाओं के पुनर्निर्धारण के माध्यम से शक्ति संतुलन का निर्माण – ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, रूस और ब्रिटेन प्रमुख आधार-स्तम्भ बने।
- राष्ट्रीयता की अनदेखी :
  - इटली एवं जर्मनी को विखंडित रखा गया, एकीकरण के आंदोलन दबा दिए गए।
  - पोलैंड की स्वतंत्रता की माँग अस्वीकार कर उसे रूस के प्रभाव में रखा गया।

    - 1820, 1830 व 1848 की क्रांतियाँ जनाकांक्षाओं की उपेक्षा के प्रतिरोध स्वरूप सामने आईं।
    - उदारवादी संविधान (स्पेन, नेपल्स) का दमन शासकों और प्रजा के बीच खाई को और चौड़ा कर गया।
- आलोचनात्मक विश्लेषण :
    - वियना समझौता राजवंशीय वैधता (Dynastic Legitimacy) को जनता की इच्छा से अधिक महत्व देता था।
    - यद्यपि लगभग चार दशकों तक शांति बनी रही, परंतु अंततः दबी हुई आकांक्षाएँ हिंसक आंदोलनों में परिवर्तित हुईं।
    - जर्मनी (1871) और इटली (1861) का एकीकरण अंततः वियना व्यवस्था को पलट गया।
- निष्कर्ष :
    - वियना कांग्रेस रूढ़िवादी ताक़तों की विजय थी पर प्रगतिशील दिशा में असफलता रही।
    - यह ज़ोर करती है कि वास्तविक राजनीतिक स्थिरता तभी बनी रह सकती है जब जनता की राष्ट्रीय और उदारवादी आकांक्षाओं को सम्मान मिले।

GS–2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

प्रश्न 2.

"उभरती हुई अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता (Rivalry) के बीच भारत की सामरिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy) की परीक्षा हो रही है।" भारत की विदेश नीति विकल्पों के संदर्भ में विवेचना कीजिए।

उत्तर का रूपरेखा (≈320 शब्द)

- परिचय :
    - सामरिक स्वायत्तता का अर्थ है किसी शक्ति-गुट से बँधे बिना स्वतंत्र निर्णय करने की क्षमता।
    - अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता (व्यापार, प्रौद्योगिकी, भू-राजनीति) भारत को नाजुक स्थिति में रखती है: एक ओर अमेरिका से निकटता बढ़ाना, तो दूसरी ओर चीन से न्यूनतम कार्यसंबंध बनाए रखना।
- भारत के सामने चुनौतियाँ :
    - चीन से सीमा तनाव (उदा., गलवान संघर्ष 2020) भारत को अमेरिका व क्वाड (QUAD) की ओर झुकाता है।
    - दवा उद्योग हेतु सक्रिय औषधि संघटक (APIs), इलेक्ट्रॉनिक्स आदि में चीन पर निर्भरता।
    - अमेरिका के साथ गहरे होते रक्षा समझौते (LEMOA, COMCASA, BECA) – जिनसे सामंजस्य (Interoperability) बढ़ता है, परंतु अत्यधिक निर्भरता का भय भी रहता है।
- भारत की संतुलनकारी नीति :
    - इंडो-पैसिफिक में स्वतंत्रता हेतु अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड साझेदारी, परंतु औपचारिक सैन्य गठबंधन से दूरी।
    - ब्रिक्स (BRICS), शंघाई सहयोग संगठन (SCO) जैसे बहुपक्षीय मंचों पर चीन से जुड़े रहना।
    - रूस से रक्षा आपूर्ति बनाए रखना, पश्चिमी दबाव के बावजूद।
    - 'पड़ोसी प्रथम' (Neighbourhood First) नीति और आसियान सहयोग से चीन के प्रभाव को संतुलित करना।
- अवसर :
    - अमेरिका–चीन संघर्ष से आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण का अवसर, विदेशी निवेश भारत में आकर्षित हो सकता है।
    - गुट-निरपेक्ष परंपरा तथा "वैश्विक दक्षिण" (Global South) के प्रतिनिधि स्वर के रूप में भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता बढ़ी है।
- निष्कर्ष :
    - भारत रणनीतिक साझेदारी और सतर्क संतुलन दोनों का सहारा ले रहा है।
    - आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat), बहु-संरेखण (Multi-alignment), तथा आंतरिक सामर्थ्य–वृद्धि के माध्यम से ही भारत सामरिक स्वायत्तता को बनाये रख पाएगा और इंडो–पैसिफिक व्यवस्था को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभा सकेगा।

GS–3 (पर्यावरण)

प्रश्न 3.

"भारत की ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) की खोज को उसकी जलवायु प्रतिबद्धताओं (Climate Commitments) के साथ संतुलित होना चाहिए।" हाल की नीतिगत पहलों के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए।

उत्तर का रूपरेखा (≈310 शब्द)

- परिचय :
    - भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है।
    - तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण ऊर्जा सुरक्षा (किफ़ायती व विश्वसनीय ऊर्जा) और जलवायु लक्ष्य (पेरिस समझौता, नेट ज़ीरो–2070) के बीच विरोध सामने आता है।

- ऊर्जा सुरक्षा के पक्ष :
  - विद्युत उत्पादन हेतु कोयले पर अत्यधिक निर्भरता (≈70%)।
  - तेल आयात बिल बढ़ने से व्यापार संतुलन प्रभावित।
  - ग्रामीण–शहरी विकास हेतु 24×7 विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता।
- जलवायु प्रतिबद्धताएँ :
  - NDC लक्ष्य : 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता 45% घटाना।
  - 2030 तक 500 GW नॉन-फॉसिल क्षमता।
  - हरित हाइड्रोजन मिशन, विद्युत वाहनों (EVs) की नीति।
- संतुलन के प्रयास :
  - कोयले का पूर्ण परित्याग नहीं, बल्कि *Phase-down*, जिसमें अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल संयंत्र शामिल।
  - ऊर्जा विविधीकरण : सौर, पवन, जलविद्युत, परमाणु विस्तार।
  - ऊर्जा दक्षता योजनाएँ : PAT योजना, EESL कार्यक्रम।
  - वित्तीय साधन : कार्बन बाज़ार, ग्रीन बॉण्ड।
- चुनौतियाँ :
  - अक्षय ऊर्जा में उच्च प्रारम्भिक निवेश।
  - ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी की कमी।
  - कोयला–आधारित क्षेत्रों में *Just Transition* की सामाजिक चिंताएँ।
- निष्कर्ष :
  - भारत नीति–गत रूप से संतुलित दृष्टिकोण अपना रहा है।
  - सस्ती और प्रचुर ऊर्जा उपलब्ध कराने के साथ ही धीरे-धीरे कार्बन तीव्रता को कम किया जा रहा है।
  - वैश्विक वित्त, घरेलू सुधार तथा प्रौद्योगिकी पर पकड़ ही तय करेगी कि भारत ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु प्रतिबद्धता दोनों को कैसे संगठित कर पाता है।

GS–4 (नैतिकता एवं प्रशासनिक ईमानदारी)

प्रश्न 4.
"लोक प्रशासन में प्रक्रियागत शुद्धता (Procedural Propriety) का पालन आवश्यक है, किंतु यह वास्तविक न्याय (Substantive Justice) की प्राप्ति में बाधा नहीं बनना चाहिए।" उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
उत्तर का रूपरेखा (≈320 शब्द)

- परिचय :
  - प्रक्रियागत शुद्धता का अर्थ है निर्णय–निर्माण में विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन।
  - वास्तविक (Substantive) न्याय का तात्पर्य है – निष्पक्षता एवं समानता पर आधारित परिणाम।
  - यदि प्रक्रियाओं का अत्यधिक कठोर पालन किया जाए तो न्याय में विलंब या वंचना संभव है।
- प्रक्रियागत शुद्धता का महत्व :
  - पारदर्शिता, जवाबदेही, और मनमानी से सुरक्षा।
  - विधि के शासन और नागरिकों के विश्वास को बनाए रखना।
- अत्यधिक बल देने की सीमाएँ :
  - लालफीताशाही और नौकरशाही सुस्ती।
  - मानवीय परिप्रेक्ष्य की उपेक्षा – जैसे वास्तविक पात्र को केवल एक प्रमाणपत्र की कमी से पेंशन न मिल पाना।
  - न्याय वितरण में विलंब (न्यायालयी प्रक्रियाएँ)।
- उदाहरण :
  - खाद्य अधिकार योजना : आवश्यक प्रमाणपत्रों की कठोरता से वास्तविक पात्र लोग वंचित रहे, बाद में प्रक्रिया शिथिल की गई।
  - कोविड संकट : वैक्सीन व राहत प्रावधान हेतु त्वरित स्वीकृति, औपचारिक प्रक्रियाओं को सीमित किया गया।
  - पर्यावरण स्वीकृति : महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं में वास्तविक जनहित के मामलों में प्रक्रिया को लचीला बनाना आवश्यक।
- नैतिक दृष्टिकोण :
  - उपयोगितावाद : त्वरित एवं अधिकतम जन–कल्याण हेतु प्रक्रियाओं में लचीलापन उचित।
  - गाँधीजी का दृष्टिकोण : नियम जनता की सेवा हेतु हैं, न कि उन्हें बंधक बनाने के लिए।
  - प्रशासनिक आचरण : वैधानिकता और सहानुभूति का संतुलन जनता का विश्वास बढ़ाता है।
- निष्कर्ष :
  - प्रक्रियागत शुद्धता आवश्यक है परंतु इसे वास्तविक न्याय में बाधक नहीं बनने देना चाहिए।

- नागरिक–केंद्रित सुधारों, उत्तरदायित्व तंत्र और नैतिक विवेक से ही दोनों लक्ष्यों में संतुलन संभव है।

समसामयिक मुद्दे

प्रश्न 5.

"भारत का अपशिष्ट प्रबंधन संकट, तकनीकी सीमाओं से अधिक शासन–संबंधी विफलताओं को दर्शाता है।" विवेचना कीजिए।

उत्तर का रूपरेखा (≈330 शब्द)

- परिचय :
  - भारत प्रतिदिन 1.6 लाख टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जिनमें से केवल 25% का ही वैज्ञानिक निपटान हो पाता है।
  - तकनीक उपलब्ध होने के बावजूद अपर्याप्त क्रियान्वयन ने संकट को गहरा किया है।
- शासन–संबंधी विफलताएँ :
  - नगरीय निकायों की वित्तीय एवं प्रशासनिक क्षमता की कमी।
  - स्रोत पर पृथक्करण न होना – प्रवर्तन और नागरिक जागरूकता में कमी।
  - केंद्र व स्थानीय स्तर पर योजनाओं में समन्वय का अभाव।
  - नियम–निर्देशों की कमजोरी – अपशिष्ट–से–ऊर्जा संयंत्र विफल क्योंकि पृथक कचरा समय पर नहीं मिलता।
  - असंगठित क्षेत्र (रैगपिकर्स) की उपेक्षा, जबकि वे पुनर्चक्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- तकनीकी क्षमता :
  - कचरे से ऊर्जा, बायोमीथेनेशन, कम्पोस्टिंग संयंत्र उपलब्ध हैं परन्तु पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा।
  - स्मार्ट बिन, सेंसर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित छँटाई का प्रयोग कुछ शहरों (इंदौर, पुणे) में।
  - इंदौर, अंबिकापुर जैसे शहरों ने सिद्ध कर दिया कि तकनीक तब सफल होती है जब शासन मजबूत हो।
- पर्यावरणीय प्रभाव :
  - वायु प्रदूषण – खुले में जलाने से विषैली गैसें।
  - जल प्रदूषण – लिचेट से भूजल प्रभावित।
  - स्वास्थ्य खतरे – डेंगू, कॉलरा जैसी बीमारियों का प्रसार।
- मार्ग–प्रशस्ति :
  - नगरीय निकायों को वित्तीय स्वायत्तता और सक्षम संसाधन।
  - स्रोत पर अनिवार्य पृथक्करण, दंड व प्रोत्साहन दोनों के सहारे।
  - असंगठित श्रमिकों को कानूनी मान्यता एवं सामाजिक सुरक्षा।
  - नागरिक सहभागिता व व्यवहार परिवर्तन हेतु जागरूकता।
  - विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) – प्लास्टिक, ई–कचरे हेतु निर्माताओं को उत्तरदायी बनाना।
- निष्कर्ष :
  - अपशिष्ट प्रबंधन संकट मुख्यतः संस्थागत असफलता है, तकनीकी कमी नहीं।
  - राजनीतिक इच्छाशक्ति, नागरिक सहभागिता और विकेंद्रीकृत शासन से भारत मॉडल शहरों के अनुभव को पूरे राष्ट्र में लागू कर सकता है तथा "परिपत्रीय अर्थव्यवस्था" (Circular Economy) की ओर अग्रसर हो सकता है।